Sixteenth Loksabha

pan>

Title: Need to direct Food Corporation of India to fix the minimum support price of paddy crop.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को सदन में रखना चाहता हूं, जो तात्कालिक, लोक-महत्व का तथा अविलंबनीय भी है। अभी भारत के प्रधानमंत्री ने किसानों के उत्पादन लागत को डेढ़ गुणा करने के लिए धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइज 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है। उसी तरह से तिलहन, दलहन सहित अन्य उत्पादों का एमएसपी भी लगभग दो सो रुपये से लेकर चार-पाँच हजार रुपये तक बढ़ाया है। हमारी सरकार की यह मंशा है कि हम किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना कर देंगे, लेकिन धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित होने के बाद भी किसानों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान को मिलर खरीदते हैं, उसके बाद उसे एफसीआई लेती है। वह कहती है कि सौ किलोग्राम धान में आपको 67 किलोग्राम चावल दे रहा है, लेकिन वह 62-63 किलोग्राम से ज्यादा नहीं पड़ता है। इसके कारण पिछले साल भी मिलर्स ने धान को बहुत दिनों तक नहीं खरीदा, जिससे हमारे धान की खरीद प्रभावित हुई । एक तरफ केन्द्र सरकार इसके दाम को बढ़ा रही है ताकि किसान को उत्पादन-लागत का डेढ़ गुणा दाम मिले ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से खाद्य एवं रसद मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि वह फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया से कहें कि धान के मामले में चावल का जितना दाम पड़ता है, वह उसे 67 किलोग्राम से घटाकर 62-63 किलोग्राम करें, जिससे किसान का धान खरीदा जा सके और उसको सरकार द्वारा घोषित मिनिमम सर्पोट प्राइस मिल सकें। धन्यवाद ।

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री निहाल चन्द तथा श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।